आकाशवाणी शिमला
05.12.2025 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

कैग रिपोर्ट

प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेल रही हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था दबाव में है और जहां प्राकृतिक आपदाओं से खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं जीएसटी दरों में बदलाव व उत्पादन शुल्क प्राप्तियों में भी कमी से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा है। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत एफआरबीएम रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4 दशमलव सात–चार फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष में प्रदेश का राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों में प्रस्तावित 10 हजार 3 सौ 37 करोड 97 लाख रुपए के मुकाबले बढ़कर 12 हजार एक सौ 14 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इससे इस वित्त वर्ष में ही राजकोषीय घाटे में एक हजार 7 सौ 76 करोड़ रुपए का और इजाफा होगा। लगातार बढ़ता राजकोषीय घाटा प्रदेश सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और घाटे को पूरा करने व राजस्व बढ़ाने के उददेश्य से विशेषज्ञों ने प्रदेश में कर व गैर कर राजस्व में बढ़ोतरी का सुझाव दिया है और साथ ही प्रदेश सरकार भी केंद्र प्रायोजित स्कीमों व परियोजनाओं के तहत अधिक से अधिक धन जुटाने का प्रयास करेगी। एफआरबीएम की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में वेतन व पेंशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा है।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमकेयर योजना के तहत बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार सीएजी से इसकी जांच करवा रही है। इसमें महालेखाकार द्वारा ऑडिट भी शामिल है। विधानसभा में प्रश्नकाल दौरान विधायक विनोद कुमार और त्रिलोक जम्वाल के संयुक्त सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमकेयर योजना के तहत अभी तक निजी अस्पतालों का 2 सौ 11 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है, जबकि एक सौ 10 करोड़ रुपए शेष है और कुल मिलाकर हिमकेयर के तहत 2 सौ 80 करोड़ रुपए का भुगतान करने को है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 2 सौ 50 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत सिर्फ उतना ही इलाज रोगियों का करेगी, जितना पैसा केंद्र से आएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार भविष्य में आयुष्मान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अब कोई पैसा खर्च नहीं करेगी और आयुष्मान भारत योजना पर प्रदेश सरकार की ओर से खर्च की जाने वाली राशि को हिमकेयर पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र से सिर्फ 43 करोड़ रुपए ही मिले है, जबकि प्रदेश सरकार इस योजना पर एक सौ 10 करोड़ रुपए तक खर्च कर चुकी है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य सरकार जलशक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स को 8 साल में दैनिक भोगी बनाने की नीति लाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में विधायक आरएस बाली द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में यह घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों को दैनिक भोगी बनाने के लिए 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और पैरा मल्टी पर्पस वर्कर के लिए कोई नीति नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में विभाग में कार्यरत इन सभी कर्मचारी वर्गों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करते हुए 8 साल में दैनिक भोगी बनाने की नीति पर

विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मानवता के आधार पर इन कर्मचारियों के लिए सरकार यह पॉलिसी लाने के बारे में सोच रही है, जिससे इन्हें राहत मिल सकेगी।

सत्र सम्पन्न

प्रदेश विधानसभा का आठ दिवसीय शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के तपोवन में सम्पन्न हो गया। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्रों में ये सबसे लंबा सत्र था। इन आठ बैठकों के साथ ही प्रदेश विधानसभा के कैलेंडर वर्ष में निर्धारित न्यूनत्तम 35 बैठकों का लक्ष्य भी पूरा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मौके पर कहा कि शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 34 घंटे चली। इस तरह सदन की उत्पादक 85 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के बाद पहली बार इस साल विधानसभा की 35 बैठकों का लक्ष्य पूरा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान 3 सौ 76 तारांकित और एक सौ 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। नियम 61 के तहत दो और नियम 62 के तहत 10 विषयों पर चर्चा हुई जबकि नियम 67 के तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव पर काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से पांच घंटे आठ मिनट चर्चा हुई जिसमें 18 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सत्र के दौरान 6 बिल पेश व पारित किए गए जबकि एक विधेयक को सदन की चयन समिति को विचार के लिए सौंपा गया।